



भारत का राजापत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

मई दिल्ली, शनिवार, विसम्बर 15, 1990/प्रग्रहायण 24, 1912

No. 718] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1990/AGRAHAYANA 24, 1912

इस भाग में भिन्न पाठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और बन मंत्रालय
(पर्यावरण, बन और बन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1990

का.आ. 944(अ):—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (मंत्रालय)
प्रविनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के
खंड (5) के मात्र परिवर्त उपधारा (1) वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग
करते हुए, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए और यह मुनिसिप्यन करने
के लिए कि तटीय क्षेत्रों में प्रयोग और फ़िकाक्साप पर्यावरणीय मंत्रालय
के सिद्धांतों और प्रोत्साहनों से संगत है, आवश्यकता पर विनाए करने के
पश्चात् प्रस्थापना करती है कि समुद्रों, खाड़ियों, झागर, मंसारों और संकरे
खाड़ियों के ऐसे नदों पर आयामों को जो उच्च ज्वार रेखा से 300 भोटर
तक स्थित की ओर ज्वारी किया से प्रभावित है तथा निम्न ज्वार रेखा
और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को तटीय विनियमन परिक्रेत के
रूप में घोषित विज्ञा जाए और उक्त तटीय विनियमन परिक्रेत में

उद्योगों की स्थापना, संकरीय या संसाधनों आदि पर निम्नलिखित निर्दिष्ट
अधिरोपित किए जाएं, अर्थात्:—

१. प्रान्तिक विद्युत क्रियाकलाप।

निम्नलिखित क्रियाकलाप तटीय विनियमन परिक्रेत के भीतर प्रतिष्ठित
किए जाने हैं, अर्थात्:—

- (i) ऐसे उद्योगों की छोड़कर, जो नीचे तटीय नगर भाग में
संवर्धित हैं या जिन्हें उठाय सुविधाओं की आवश्यकता है
उद्योगों की स्थापना;
- (ii) भारत सरकार के पर्यावरण और उन मंत्रालय की अधिसूचनाओं
में, का.आ. 594(अ), तारीख 28 जुलाई, 1989 का.आ. 966 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 1989 और का.नि.प्रा.
1037(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 की अधिसूचनाओं
में विनियोग रूप में परिवर्कमप पदार्थों का विनिर्माण या
होलिना या संग्रहण या व्यय;
- (iii) मल्य संसाधन इकाइयों जिनके ग्रन्तिगत भाड़ारकरण भी है।
- (iv) अपशिष्टों और बहिःस्थावरों के व्ययन के लिए इकाइयों यांत्रिकों
की स्थापना;

- (v) उद्योगों, नगरों या पाल्यों और अस्थि मानव अवस्थाओं में प्राथमिक अपशिष्ट और वहिद्वारों का निस्सारण;
- (vi) भूमि भरने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा नगर निगम अपशिष्ट का लेप करना;
- (vii) तात्त्विक विद्युत केंद्रों से, गाँव का लेप करना,
- (viii) समृद्ध जल के प्राकृतिक क्षम को सम्पूर्ण ज्ञानाभ्यों के साथ धोका फरना या उसमें बाधा बालना सिवाए, उसके बीच लटीव फटाव के नियंत्रण के लिए अपेक्षित है;
- (ix) भूमि पुनर्गार, बालू, घटानों और अस्थि अवस्थर सामग्री की बचनीकरण;
- (x) भूस्थि संप्रहण या भूजल का निकालना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका सम्मिलित या यांत्रिकी;
- (xi) उपार्थ में विनिविष्ट रूप में पारिस्थितिक रूप से मुद्रांकी धोकों में सम्मिलित क्रियाकलाप;
- (xii) निर्मल ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच कोई सम्मिलित क्रियाकलाप; और
- (xiii) बालू टिक्का, पहाड़ों, प्राकृतिक विशेषताओं की भजायट अथवा उसमें परिवर्तन करना जिसके अन्तर्गत सुन्दर बनाने मनोरंजन नवीनी और अन्य प्रयोजनों के लिए भूमध्य परिवर्तन भी हैं।

3. अनुरेप क्रियाकलापों का विनियमन।

अस्थि सभी क्रियाकलाप, उनके सिद्धाय जो ऊपर पैरा 2 में प्रतिविष्ट हैं निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:—

(1) तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर किसी क्रियाकलाप के लिए अनुसा केवल सभी यी जाएगी जब तिरचायक रूप से वह साधित हो जाए कि ऐसा क्रियाकलाप परिक्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं किया जा सकता है।

(2) निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय यी अनुसा अपेक्षित होती है; प्रथमतः—

(i) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित सम्मिलित क्रियाकलाप जिनके लिए तट समाप्त सुविधाएं मांवधक हैं (उदाहरणार्थ जलावृत्तरण मंच, जैवी आवि);

(ii) ऐसे पत्तों और बन्दरगाहों तथा प्रकाश स्तरों के लिए मक्कियास्मक सन्दिग्धत जिनके लिए नन अप्रभाग अपेक्षित हैं;

(iii) तात्त्विक विद्युत संयंत्र; और

(iv) पांच करोड़ रुपय से अधिक विनियोग वाले अन्य सभी क्रियाकलाप।

(3) (i) तटीय राज्य और संच राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर उपार्थ 1 में दिए गए मानवर्दीक सिद्धांतों के अनुसार तटीय आयामों का पता लेकार और उनका नवीनीकरण करके तटीय परिक्षेत्र प्रबन्ध योग्यता दीपार करें और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय का अनुभोग अधिकार्यत करें तथा भूमि उपयोग जाति पर सुरक्षा कानूनों और विनियमों में इन्हें सम्मिलित करें।

(ii) ऐसी अनुमोदित योजनाओं जो रूपरेखा के भीतर जो क्रियाकलाप ऊपर पैरा 2 और पैरा 3(2) में सम्मिलित नहीं हैं, वे उपार्थ 1 में दिए गए मानवर्दीक सिद्धांतों के अनुसार यथाविधि, राज्य सरकार, संच राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

4. मानीटर करने और प्रबंधन के लिए प्रक्रिया:—

पर्यावरण और बन मंत्रालय, तथा राज्य सरकार या संच राज्यक्षेत्र स्तरों पर ऐसे अस्थि प्राधिकरण, जो इस

प्रयोजन के लिए अधिकृत किए जाएं, इस अधिसूचना के संशोधित नामों को मानीटर करने और उनके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. आधिकारिक मानीटर:

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसा कोई अधिकृत, जो प्रस्तावित नियमों के विरुद्ध कोई आंदोलन करने का इच्छुक है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय पर्यावरण, बन और अन्य जीव विभाग, नई दिल्ली के सचिव को विवित में ऐसा कर सकेगा।

[ए.के. 15019/1/84-प्राहृष्ट ए-III (गिर्ल)]
महेश प्रसाद, सचिव

अनुबन्ध-1

तटीय ज्वार रेखा और विकास नियमन

नटकर्ता नियमन क्षेत्र का वर्गीकरण

6(1) विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के नटकर्ता भागों को आंदोलनों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथमतः—

श्रेणी-1. (सी.आर.जे.ड-1):—

राष्ट्रीय उथानों, अभ्यासरथ्यों, प्रारंभिक वनों, कबूल बनस्पति, मूर्ग मछली और अस्थि समुद्री जीवों के प्रजनन क्षेत्र और अंडे देने वाली भूमि प्राकृतिक मुन्दरता वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थान और बन मंत्रालय या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अस्थि क्षेत्र।

श्रेणी-2. (सी.आर.जे.ड-2):—

समुद्री किनारों या उनके नजदीक तक पहुँचे ही से विकसित क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए “विकसित क्षेत्र” का आगम नगरीय सीमाओं के अन्दर उस क्षेत्र से है जहां पहुँचे ही काफी निर्माण हो सका है और जहां अस्थि विकासी और पुनर्वासन तथा जल अपूर्ति और मूल्य मलजल निकास जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

श्रेणी-3. (सी.आर.जे.ड-3):—

वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत शात क्षेत्र हैं और जो श्रेणी-1 व 2 के अन्तर्गत नहीं माते हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र (विकसित और अविकसित) और नगरीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र आयेंगे, जहां पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

श्रेणी-4. (सी.आर.जे.ड-4):

सी.आर. जे.ड-1, सी.आर. जे.ड-2 और सी.आर. जे.ड-3 में विनिविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अंडमान और निकोबार तथा अक्षरीय समूह के नटीय भाग।

गतिविधियों के नियमन के लिए मापदंड:

6(2) नटीय भागों की विभिन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

सी.आर. जे.ड-1

उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के माध्यमिकी नन निर्माण की अनुमति नहीं है।

प्रारंभिक-2

- (1) जहाँ भूद्वे के किनारे और विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित थेक्स को शैलग करने वाला कोई मार्ग है उस स्थिति में विद्युत मान भार्गो के भूमि की ओर ही नए निर्माण की अनुमति दी जाए, वश्वते कि एक एस आई/एप ए आर के लिए विद्युत मान भवनों सहित स्थानीय टाउन और कंट्री ज़ानिंग विनियमों का पालन किया जाए।
- (2) जहाँ किनारे के क्षेत्रों तथा आसपास के विकास को ध्वनि करने वाला कोई मार्ग नहीं है, उस स्थिति में भीजूड़ा, संरचनाओं के यथृद्वे की ओर स्थानीय टाउन एंड कंट्री ज़ानिंग विनियमों के अन्वेषण भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (3) विद्युत मान एक एस आई/एप ए आर मापदंडों का अनुपालन करने और विद्युत मान प्रयोग में परिवर्तन किए बिना प्राधिकृत भवनों के पुनः निर्माण की अनुमति दी जायेगी।
- (4) भवनों को अधिकल्प और निर्माण स्थानीय वास्तुकला और प्राकृतिक दृष्टियों के अनुलूप होना चाहिए।

प्रारंभिक-3

- (1) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के थेक्स को "विकास थेक्स नहीं" माना जाना है और इस थेक्स के अन्वर किनों भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) अनुबन्ध-2 में डिलिखित विभाग-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन किए गए आसपास होटल/समूह किनारों पर सेराहाह हालिंड हांग्स के निर्माण के लिए उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर 500 मीटर के बीच के खाली प्लाटों के विकास की अनुमति है।
- (3) उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर 500 मीटर के बीच आवास इकाइयों के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति है वश्वते कि यह परम्परागत प्रविकारों और प्रयोगों की परिधि में पाला हो। इस प्रकार के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति अनुबन्ध-2 में लिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार दी जायेगी।
- (4) उपरोक्त (1) से (3) की शर्त पर विद्युत मान प्राधिकृत भवन के पुनः निर्माण/उसमें परिवर्तन करने की अनुमति है।

प्रारंभिक-4

संरक्षण और निकारार द्वीप समूह:

- (1) उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर भवन के अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) उच्च ज्वार सीमा से 200 तथा 500 मीटर के बीच स्थित भवन 2 तल (निवास तल और प्रथम तल) से प्रधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए, कुप्र आचारित थेक्स भूमि के टुकड़े का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा उस स्थान के परिषुद्ध से मेल जाना चाहिए।
- (4) तटों और तटीय जल की मूँगा चट्टानों तथा बाढ़ की निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- (5) मूँगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलमार्जन तथा जल के भीतर लिस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा
- (6) मूँगा द्वीपसमूहों में तटीय भार्गों की भी सी. आर. जेड-1 प्रथमा 2 प्रथमा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भार्गों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे।

संरक्षण समूह

- (1) अवन निर्माण की अनुमति देते समय द्वीप समूहों के आकार के अनुसार उच्च ज्वार सीमा की दूरी निर्धारित करनी चाहिए। इसका नियोगिता विशेषज्ञों के परामर्श से जल-नियामीय पहलुओं, भूमि काटाव तथा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता सहित स्थानीय परिस्थितियों की तुलना में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग का आवश्यकतामयों को ध्वनि ने रखते हुए प्रत्यक्ष द्वीप के लिए किया जाना चाहिए।
- (2) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के भवन 2 तल (निवास तल तथा प्रथम तल) से प्रधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। कुप्र आचारित थेक्स भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से प्रधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा परिषुद्ध से मेल जाना चाहिए।
- (4) तटों तथा तटीय जल की मूँगा चट्टानों तथा बाढ़ को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- (5) लैगून तथा मूँगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलमार्जन जल के भीतर लिस्फोट करने की अनुप्रसिद्धि नहीं दी जानी चाहिए तथा।
- (6) तटीय भार्गों में तटीय भार्गों को भी सी. आर. जेड-1 प्रथमा 2 प्रथमा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भार्गों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे।

अनुबन्ध-2

तटीय भार्गों में समुद्रनाट सैर-गाह/होटल/आवास-गृह के लिए मार्ग-निर्देश

7. (1) तटीय भार्गों में समुद्रनाट सैर-गाह/होटल/आवास-गृह के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं।
 - (1) परियोजना प्रस्तावक उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक (भूमि की सी) तथा निम्न ज्वार और उच्च ज्वार सीमा के बीच के थेक्स में कोई निर्माण कार्य (स्थायी निर्माण और कंट्रील जल ग्राम्य इस प्रकार के अन्य भवनों सहित) नहीं किये जाएं।
 - (2) आचारित थेक्स प्लाट के आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। युक्त थेक्स में उपयुक्त हस्तियालों से महीं तरंगों से मूँड़ाय निर्माण किया जाना चाहिए।
 - (3) निर्माण आवास-पास के भू-पृष्ठ तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए।
 - (4) भवन का कुल ऊंचाई 9 मीटर से प्रधिक नहीं होनी चाहिए और भवन दो मंजिलों (भूमि तल और प्रथम तल) से प्रधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए।
 - (5) कंट्रीम/राज्य भूमि जल बोर्ड की सहमति के लिए पूरी जल एवं दी.एल. से 500 मीटर के आदर से नहीं लिया जाना चाहिए।
 - (6) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर भवन, तरणताल, तथा घेसमेंट, के बुनियादी द्वांवे के अलावा रेत लिकासने देनीले भार्गों को समतल बनाने या बुढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- (7) परियोजना क्षेत्र से शोधित बहिनावांकों द्वारा अपशिष्टों उत्पादनों की अवाली और और स्तर भावित समान प्राधिकरणों, जिसमें केन्द्रीय राज्य प्रशूलण नियंत्रण बोर्ड शामिल है तथा पर्यावरण (मुख्या) अधिनियम 1986 द्वारा निर्धारित मानकों के प्रत्युष होना चाहिए।
- (8) बहिनावांकों और टोस अपशिष्टों के शोधन के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ न किए गए बहिनावांकों और टोस अपशिष्टों को जल गा ममत्वी किनारों पर न भाहया जाए।
- (9) सोग समुद्री किनारों तक आ सके, इसके लिए किन्होंने प्लाटों के शीख कम से कम 20 मीटर औरी पट्टी मूँह्या कराई जाए; और,
- (10) यदि परियोजना में वर्तन्तेर प्रयोजनों के लिए बन भूमि की उपयोग में लाया जाना हो तो इसके लिए बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है। परियोजना के संबंध में लागू अन्य केन्द्रीय और राज्य कानूनों का अनुपासन किया जाना चाहिए।

7(2) परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे मेरीन पार्क, कर्ण वनस्पति, भूगोल चट्टानें, मछलियों के प्रजनन और अंडे देने की जगह तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अंडे) समुद्री सैरगाहों/होटलों प्रावासों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महेश प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1990

S.O. 944 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after considering the need for protecting the coastal areas and for ensuring that the use and activities in the coastal areas are consistent with the principles and requirements of environmental conservation, hereby proposes to declare that the coastal stretches of seas, bays, estuaries and creeks which are influenced by tidal action (in the landward side) upto 500 metres from the High Tide Line and the land between the Low Tide Line and the High Tide Line as Coastal Regulation Zone and to impose the following restrictions on the setting up of industries, operations or processes etc. in the said Coastal Regulation Zone, namely:—

2. Prohibited Activities

The following activities are declared as prohibited within the Coastal Regulation Zone, namely:—

- setting up of industries except those directly related to sea front or directly needing foreshore facilities;
- manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Notifications of the Govt. of India in the Ministry of Environment and Forests

- No. S.O. 594 (E) dated 28th July, 1989
S.O. 966 (E) dated 27th November, 1989
and GSR 1037 (E) dated 5th December, 1989;
- fish processing units including warehousing;
 - setting of units/mechanisms for disposal of wastes and effluents;
 - discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities or towns and other human settlements;
 - dumping of municipal waste for the purposes of landfilling or otherwise;
 - dumping of ash from thermal power stations;
 - bunding or disturbing the natural course of sea water with similar obstructions, except those required for control of coastal erosion;
 - land reclamation, mining of sands, rocks and other substrate materials;
 - harvesting or drawal of ground water and constructions or mechanisms thereof for such purposes;
 - construction activities in ecologically sensitive areas as specified in Annexure;
 - any construction activity between the Low Tide Line and High Tide Line; and
 - dressing or altering of sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreational and other such purposes;

3. Regulation of Permissible Activities.

All other activities, except those prohibited in para 2 above, will be regulated as under:

- Clearance shall be given for any activity within the Coastal Regulation Zone only if it is proved conclusively that such activity cannot be located beyond the zone.
- The following activities will require clearance from the Ministry of Environment and Forests, Government of India, namely:
 - Construction activities related to Defence requirements for which foreshore facilities are essential (e.g. slipways, jetties etc.);
 - operational constructions for ports and harbours and light houses requiring water frontage;
 - thermal power plants; and
 - all other activities with investment exceeding rupees five crores.
- (i) The coastal States and Union Territory Administration shall prepare Coastal Zone Manage-

ment Plans identifying and classifying the coastal stretches within their respective territories in accordance with the guidelines given in Annexure-I and obtain approval of the Central Govt. in the Ministry of Environment and Forests and incorporate these in the relevant statutes and regulations on landuse etc.

(ii) Within the frame work of such approved plans, the activities not covered in para 2 and para 3 (2) above shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration or the local authority as the case may be, in accordance with the norms given in annexure-I.

4. Procedure for monitoring and enforcement

The Ministry of Environment and Forests and the Government of State or Union Territory and such other authorities at the State or Union Territory levels, as may be designated for this purpose, shall be responsible for monitoring and enforcement of the amended provisions of this notification.

5. Inviting objections

It is notified under clause (b) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, that any person interested in filing any objection against the proposed direction, may do so in writing to the Secretary in the Department of Environment, Forests and Wildlife, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, within sixty days from the date of publication of this notification in the official gazette.

[No. K-15019/1/84-IA-III (Vol.II)]
MAHESH PRASAD, Secy.

ANNEXURE I

COASTAL AREA CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT REGULATIONS

Classification of Coastal Regulation Zone:

6(1) For regulating development activities, the coastal stretches within 500 metres of High Tide Line on the landward side are classified into four categories, namely:—

Category I (CRZ-I) :

Areas that are ecologically sensitive and important, such as national parks, sanctuaries, reserve forests, mangroves, corals, areas close to breeding and spawning grounds of fish and other marine life, areas of outstanding natural beauty and such other areas as are notified by the Central Government or the concerned authorities at the State/UT level from time to time.

Category II (CRZ-II) :

The areas that have already been developed upto or close to the shore-line. For this purpose, "developed area" is referred to as that area within the municipal limits which is already substantially built up and which has been provided with drainage and approach road and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains.

Category III (CRZ-III) :

Areas that are relatively undisturbed and those which do not belong to Category-I & II. These will include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and areas within municipal limits where substantial development has not taken place.

Category IV (CRZ-IV) :

Coastal stretches in the Andaman & Nicobar and Lakshadweep island except those designated as CRZ-I, CRZ-II and CRZ-III.

Norms for Regulation of Activities :

6(2) The development or construction activities in different categories of coastal stretches shall be regulated by the concerned authorities at the State/Union Territory level, in accordance with the following norms :

CRZ-I .

No new construction permitted within 500 metres of the High Tide Line.

CRZ-II

(i) Where there is a road separating the beach and the area proposed to be developed, new constructions be permitted only on the landward side of the existing road, subject to the local Town & Country Planning Regulations including the existing norms for FSI/FAR.

(ii) Where there is no road separating the beach area and the surrounding development, construction of building shall not be allowed on the sea-ward side of the existing structures subject to the local Town and Country Planning regulations.

(iii) Reconstruction of the authorised buildings to be permitted subject to compliance with the existing FSI/FAR norms and without change in the existing use.

(iv) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape.

CRZ-III

(i) The area upto 200 metres from the High Tide Line is to be earmarked as 'No development zone' and no construction shall be permitted within this zone.

(ii) Development of vacant plots between 200 and 500 metres of High Tide Line permitted for construction of lodging houses/hotel/beach resorts/holiday homes subject to the conditions as stipulated in the guidelines at Annexure-II.

(iii) Construction/reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High

Tide Line permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses. Building permission for such construction/reconstruction will be in accordance with the guidelines at Annexure II.

- (iv) Reconstruction/alterations of an existing authorised building permitted subject to (i) to (iii) above.

CRZ-IV

Andaman & Nicobar Islands:

- (i) No construction of buildings shall be permitted within the 200 metres of the HTL;
- (ii) The buildings between 200 and 500 metres from the High Tide Line should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters should not be used for construction purposes;
- (v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations should not be permitted; and
- (vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories would apply.

Lakshadweep Islands

- (i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line should be decided depending on the size of the islands. This should be laid down for each island in consultation with the experts keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects, erosion and ecological sensitivity;
- (ii) The buildings within 500 metres from the HTL should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters, should not be used for construction purposes.

- (v) Dredging and under water blasting in and around lagoons as coral formations should not be permitted; and,
- (vi) However, in some of the Islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III. In such designated stretches, the appropriate regulations given for respective categories would apply.

ANNEXURE II

Guidelines for beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches.

7(1) Construction of beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches will be subject to the following conditions:—

- (i) The project proponents will not undertake any construction (including temporary constructions and fencing or such other barriers) within 200 metres (in the landward side) from the High Tide Line and within the area between the low tide and high tide line;
- (ii) The covered area should not exceed 33 per cent of the plot size. The open area should be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
- (iii) The construction should be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.
- (iv) The overall height of construction should not exceed 9 metres and the construction should not be more than 2 floors (ground floor plus one upper floor);
- (v) Ground water should not be tapped within 500 metres of the HTL without the concurrence of the Central/State Ground water Board;
- (vi) Extraction of sand, levelling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool and basement, should not be permitted within 500 metres of the High Tide Line;
- (vii) The quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise level etc. from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central/State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
- (viii) Necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made. It must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach;

- (ix) To allow public access to the beach, atleast a gap of 20 metres width should be provided between any two plots; and
- (x) If the project involves diversion of forests for non-forest purpose, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 should be obtained. The requirements of other Central and State laws as applicable to the project should also

be met with.

7.(2) In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other areas as notified by the Central/State Government), construction of beach resorts/hotels/lodging houses shall not be permitted.

MAHESH PRASAD, Secy.
14-12-90

